

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4554
उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

फतेहगढ़ साहिब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

4554. डॉ. अमर सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को फतेहगढ़ साहिब में बड़े उद्योगों की कमी तथा इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक समूहों की स्थापना करने अथवा नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : उद्योग, राज्य का विषय है और केंद्र सरकार, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सरकार, पंजाब में फतेहगढ़ साहिब सहित देश में एमएसएमई के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और मांग आधारित योजनाओं, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस), पीएम विश्वकर्मा, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैंप), एमएसएमई चैंपियंस योजना आदि शामिल हैं।

दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 15/03/2025 तक उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत कुल उद्यम और रिपोर्ट किए गए रोजगार				
अखिल भारत/ राज्य/ जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
अखिल भारत	60,525,085	742,780	69,711	61,337,576
पंजाब	1,677,425	27,505	2,471	1,707,401
फतेहगढ़ साहिब	32,360	1,483	387	34,230

- (i) पंजाब राज्य में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2024 में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) राजपुरा-पटियाला (1,098.85 एकड़) का अनुमोदन किया गया था, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1367.72 करोड़ रुपए है।

(ii) वित्त तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, सीजीएस के अतिरिक्त, कुछ योजनाएं जैसे कि बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना।

(iii) फतेहगढ़ साहिब जिले में पीएमईजीपी के प्रदर्शन का विवरण, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और पिछले 3 वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के संदर्भ में सृजित अनुमानित रोजगार नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	वितरित की गई एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
वित्त वर्ष 2021-22	71	156.21	568
वित्त वर्ष 2022-23	43	119.95	344
वित्त वर्ष 2023-24	41	155.81	328
